शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मंत्रिमंडल के लिए अगस्त, 2020 के महीने का मासिक सार:

1. अगस्त, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

क. नई शिक्षा नीति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। यह नीति भारत की नई शिक्षा प्रणाली के विजन को रेखांकित करती है। नई नीति, 1986 की पिछली राष्ट्रीय नीति की जगह लेती है। यह पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर बनाई गई हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **वर्ष 2035 तक जीईआर को 50% तक बढ़ाना**

एनईपी 2020 का लक्ष्य वर्ष 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% (2018) से बढ़ाकर 50% तक करना है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

- **समग्र बहुविषयक शिक्षा**

नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित अनेक प्रवेश और निकास बिंदु के साथ व्यापक आधारित, बहु-विषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। अवर स्नातक शिक्षा 3 या 4 वर्ष की हो सकती है जिसमें इस अवधि के भीतर उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ अनेक प्रवेश और निकास विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष के बाद का सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जा सकती है।

- **विनियमन**

यूजीसी, एआईसीटीई को एकल भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सम्पूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए एकल व्यापक संरक्षक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। एचईसीआई के पास चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र हैं - विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी), मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)। एचईसीआई प्रौद्योगिकी के माध्यम से अप्रत्यक्ष कार्यक्रमों के जरिए कार्य करेगा और इसके पास उच्चतर शिक्षण संस्थानों को मानदंडों और मानकों के

अनुरूप न होने के लिए दंडित करने की शक्ति होगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को नियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित किया जाएगा।

- विश्वविद्यालयों का नाम स्वामित्व के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर रखा जाएगा। बहुआयामी शिक्षा को प्रोत्साहन।

- विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिटों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी होगी ताकि इन्हें आखिर में प्राप्त की जाने वाली डिग्री के लिए अंतरित किया जा सके और उसके लिए गिना जा सके।

- बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) को आईआईटी,आईआईएम के समान ही देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहु-विषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा।

- मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्चतर शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), वास्तुकला परिषद (सीओए), व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) आदि जैसे व्यावसायिक परिषद, व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों (पीएसएसबी) के रूप में कार्य करेंगे।

- कॉलेजों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध किया जाना होगा और कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरण-वार तंत्र स्थापित करना होगा। यह परिकल्पना की गई है कि कुछ समय बाद, प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित होगा।

- **भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना**
- सभी भारतीय भाषाओं का संरक्षण, संवृद्धि और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, एनईपी पाली, फारसी और प्राकृत उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और अन्य सभी भाषा विभागों के सुदृढीकरण के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (आईआईटीआई), राष्ट्रीय संस्थान (संस्थानों) की स्थापना करने और एचईआई के अधिक कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा / स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश करता है।

- **शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण** को संस्थागत सहयोग और छात्र और संकाय गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और शीर्ष विश्व रैंक वाले विश्वविद्यालयों को हमारे देश में परिसरों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

ख. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।

इस सम्मेलन में मसौदा, एनईपी संबंधी समिति के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविदों / वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात की।

इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर, माननीय शिक्षा मंत्री ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षु/ इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम प्रदान करने के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों का वर्चुअल शुभारंभ किया।

ग. अटल रैंकिंग ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स ऑन इनोवेशन अचीव्मेंट्स (एआरआईआईए)- 2020 की शुरुआत

एआरआईआईए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की एक पहल है, जिसे छात्रों और संकायों के बीच "नवाचार और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक करने के लिए एआईसीटीई और मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन सात मापदंडों के आधार पर किया गया है। इनमें बजट और निधि सहायता, अवसंरचना और सुविधाएं, जागरूकता, प्रोत्साहन और विचार सृजन और नवाचार के लिए सहायता शामिल है।
- इस वर्ष, एआरआईआईए घोषणा में संस्थानों का दो व्यापक श्रेणियों और छह उप श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया था।
- इनमें से, IIT मद्रास ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अंतर्गत प्रथम स्थान मिला।
- कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।
- कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर को निजी अथवा स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के तहत शीर्ष स्थान मिला।

- एस आर इंजीनियरिंग कॉलेज, वारंगल को निजी अथवा स्व-वित्तपोषित कॉलेजों के तहत शीर्ष स्थान मिला।
- इस वर्ष, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाने के लिए महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों हेतु एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है। अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन ने इस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया।

घ. 5 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) सिरमौर का ई-शिलान्यास किया गया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर; वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे के साथ हिमाचल प्रदेश के धौलाकुआं में 210 एकड़ जमीन पर वर्चुअल मोड में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) सिरमौर का शिलान्यास किया।

आईआईएम सिरमौर का संचालन अगस्त 2015 से आईआईएम लखनऊ द्वारा उसके मेंटर संस्थान के रूप में शुरू किया गया था। इसका पहला बैच पौंटा साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में अपने अस्थायी परिसर से 20 छात्रों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम की शुरुआत के साथ किया गया।

धौलाकुआं में पूर्ण स्थायी परिसर 1170 की छात्र संख्या के लिए परिकल्पित किया गया है। केंद्र सरकार ने 531.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है जिसमें से 392.51 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों के लिए है।

ड. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षुता अथवा इंटर्नशिप-एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षुता अथवा इंटर्नशिप-एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, यह दिशानिर्देश उच्चतर शिक्षण संस्थानों को यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अवर स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रशिक्षुता / इंटर्नशिप शामिल करने का विकल्प प्रदान करेगा। यह डिग्री प्रोग्राम में परिणाम-आधारित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करेगा और छात्रों को संभावित रोजगार के लिए उनकी पसंद के विषयों में कार्यबल पेशेवर क्षमताओं का प्रदर्शन करने में समर्थ बनाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार-नियोजनीयता अंतर को दूर करना और उच्चतर शिक्षा प्रणाली तथा उद्योग, वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक उद्यमों / संगठनों के बीच सक्रिय संबंध को बढ़ावा देना है।

च. स्मार्ट इंडिया हैकथॉन - 2020 के चौथे संस्करण (सॉफ्टवेयर) का ग्रैंड फिनाले 4 अगस्त, 2020 को संपन्न हुआ।

देश भर के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों में 1 से 4 अगस्त, 2020 तक एक साथ हैकथॉन का आयोजन किया गया। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया में सबसे बड़े हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक ने 1 अगस्त, 2020 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (एसआईएच) -2020 (सॉफ्टवेयर संस्करण) के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया।

कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, एसआईएच के इतिहास में पहली बार ग्रैंड फिनाले का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था, जिसमें विशेष रूप से निर्मित उन्नत एसआईएच प्लेटफॉर्म पर पूरे देश से सभी प्रतिभागियों को एक साथ जोड़ा गया। एसआईएच 2020 में 1080 टीमों और 705 मेंटरों (प्रति टीम 6 प्रतिभागी, लगभग 6480 प्रतिभागी) सहित प्रतिनिधियों, जूरी सदस्यों, छात्रों, नोडल केंद्र समिति और आयोजकों सहित लगभग 10,000 सदस्यों ने भाग लिया, जिनहोने भारत के 40 से अधिक केंद्रों पर 36 घंटे तक प्रतिस्पर्धा की।

यह इस देशव्यापी पहल का चौथा संस्करण है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और इस तरह उत्पाद नवाचार की संस्कृति और समस्या को हल करने की मानसिकता विकसित करता है।

छ. जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली द्वारा गांधीवादी विचार और दर्शन पर आयोजित वेबिनार।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर आयोजित किए गए गांधीवादी विचार और दर्शन पर एक वेबिनार को संबोधित किया। यह गांधीवादी विचार और दर्शन पर वेबिनार श्रृंखला का पहला व्याख्यान था। यह वेबिनार श्रृंखला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के प्रस्ताव के अनुरूप है, जिससे गांधीवादी विचार और दर्शन को बौद्धिक दायरों में प्रचारित किया जाएगा।

ज. 11 अगस्त 2020 को सीओए (वास्तुशिल्पीय शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 का उद्घाटन और शुभारंभ

शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे सतत शैक्षिक सुधारों के अनुसरण में, शिक्षा मंत्री ने "वास्तुशिल्पीय शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम, 2020" का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये विनियम 1 नवंबर, 2020 से लागू होंगे और 1983 के विनियम को अधिक्रमित करेंगे।

वास्तुकला अधिनियम के तहत वास्तुशिल्प परिषद (सीओए) और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंड और विनियमों का पालन करना होगा, जो वास्तुकला में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है।

इन विनियमों का छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण छात्रों को कौशल को सीखने और विकसित करने से लेस करेगा जिससे वे वास्तुशिल्प के क्षेत्र में आदर्श बदलाव ला सकेंगे।

नए विनियमों के अनुसार, वास्तुशिल्प पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 5 शैक्षणिक वर्ष अथवा 10 सेमेस्टर होगी जिसमे प्रत्येक सेमेस्टर में 15 से 18 कार्य सप्ताह (90 कार्य दिवस) होंगे। पाठ्यक्रम के उम्मीदवार को परीक्षा की 10 + 2 योजना के अंत में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ और 10 + 2 स्तर की परीक्षा के कुल 50 प्रतिशत अंको के साथ अथवा अनिवार्य विषय के रूप में गणित सहित कम से कम 50 प्रतिशत के साथ 10 + 3 डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उम्मीदवार को परिषद द्वारा आयोजित वास्तुशिल्प एप्टीट्यूड टेस्ट भी उत्तीर्ण करना होगा।

झ. **विश्व उर्दू सम्मेलन**

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल) द्वारा आयोजित दो दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस वेबिनार का आयोजन उर्दू की सर्वोत्कृष्ट भावना, इसके समावेशी लोकाचार और रचनात्मक चरित्र को स्पष्ट करने के लिए किया गया था।

शिक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की और कहा कि अगले वर्ष से उर्दू परिषद द्वारा उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को अमीर खुसरो, मिर्ज़ा ग़ालिब, आगा हशर, राम बाबू सक्सेना और दया शंकर नसीम जैसी उर्दू की जानी मानी हस्तियों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ताकि साहित्यिक और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहन मिले ।

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में सुधार:

छह और विषयों - भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में पाठ्यक्रम आधारित मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। गुणवत्तापूर्ण एमओओसी के विकास के लिए 194 स्रोतों की पहचान की गई है। पाठ्यक्रम के विकास के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति मांगी गई है।

ट. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** (रूसा)

चालू वित्त वर्ष-2020-21 के दौरान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की योजना के तहत अगस्त, 2020 के दौरान राज्य सरकार को 2.25 करोड़ रुपए सहित कुल Rs.51.208 करोड़ रुपए (पहले से जारी केंद्रीय अनुदान पर ब्याज समायोजन सहित) जारी किए गए हैं।

सचिवों का क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस)

मंत्रिमंडल संचिवालय के ई-समीक्षा पोर्टल पर एसजीओएस समूह -4 के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्रवाई योग्य सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति को अपडेट करने के लिए संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एसजीओएस ग्रुप -4 के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधियों के साथ 7 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

"उच्चतर शिक्षा से संबंधित 9 कार्रवाई योग्य सिफ़ारिशों में से 3 पूरी हो चुकी हैं और 6 प्रगति पर हैं।"

सचिवों के क्षेत्रीय समूह द्वारा अंतिम रूप दिए गए 5 वर्षीय विजन दस्तावेजों में की गई सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 14 अगस्त, 2020 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के क्षेत्रीय समूह के संयोजकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

ठ. **माह के दौरान छात्रवृत्ति प्रभाग के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:**

(i) मंत्रालय की वेबसाइट पर चीनी सरकारी छात्रवृत्ति 2020-21 के संबंध में चीनी दूतावास द्वारा घोषित परिणाम को सूचित किया गया ।

(ii) वित्त वर्ष 2020-21 से, जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू-कश्मीर के लिए एसएसएस) के तहत एआईसीटीई को निधि के संवितरण हेतु एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया है।

(iii) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना के संबंध में ईएफ़सी ज्ञापन, जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना प्रस्तुत की जा रही है।

ड **शोध को बढ़ावा देना:**

सहयोगात्मक शोध अनुदान कार्यक्रम: एआईसीटीई ने 20 मार्च, 2019 को इंप्रिंट इंडिया योजना के अनुरूप फोकस राज्यों में काम कर रहे टेक्विप (टीईक्यूआईपी) संकाय के लिए सहयोगात्मक शोध योजना (396) का शुभारंभ किया था। 221 संस्थानों के 1609 शोधकर्ता 47.56 करोड़ रुपये के अनुसंधान अनुदान के साथ 396 सीआरएस परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अब तक दो समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं और अनुसंधान अनुदान का लगभग 50% वितरित किया जा चुका है। समीक्षा -1 और समीक्षा -2 में विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अथवा संस्थान से संकाय के त्यागपत्र के कारण अथवा 21-22 फरवरी 2020 को

आयोजित दूसरी समीक्षा में अनुपस्थित रहने के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 जून- 3 जुलाई 2020 के बीच आयोजित पुन: समीक्षा में भी अनुपस्थित रहने के कारण 396 सीआरएस परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। अगली समीक्षा बैठक सितंबर 2020 के मध्य तक होनी प्रस्तावित है। 130 परियोजनाओं को लगभग 4.5 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी की गई है और आगे की धनराशि जारी की जा रही है।